

प्रयुचर इंडिया 2047

अगली पीढ़ी का घोषणापत्र (The Next Generation Manifesto)

भविष्य का निर्माण करें। नागरिक को सशक्त बनाएं। राष्ट्र को मज़बूत करें।

हमारी दृष्टि

हम ऐसा भारत नहीं चाहते जहाँ किसी बच्चे का भविष्य तय होता है — जाति से, पारिवारिक धन से, धर्म से, उपनाम से, गाँव से, शहर से, राजनीतिक संबंधों से, या जन्म की संयोगवश स्थिति से।

हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ क्षमता अवसर बन सके। जहाँ गाँव का बच्चा वैज्ञानिक बन सके। जहाँ किसान उद्यमी बन सके। जहाँ एक युवती अपने समुदाय को छोड़े बिना कंपनी बना सके। जहाँ शिक्षक वास्तव में पढ़ाने योग्य हों। जहाँ सरकारी धन का पता लगाया जा सके। जहाँ भ्रष्टाचार राजनीतिक प्रभाव के पीछे न छिप सके। जहाँ नदियाँ स्वच्छ हों। जहाँ वन सुरक्षित हों। जहाँ जल एक राष्ट्रीय रणनीतिक संसाधन के रूप में नियोजित हो। जहाँ सशस्त्र बलों के पास आधुनिक भारतीय प्रौद्योगिकी हो। जहाँ किशोरों के पास केवल परीक्षा कक्ष नहीं, प्रयोगशालाएँ हों। जहाँ छात्रों के लिए शिक्षा, नवाचार और सृजन के इर्द-गिर्द शहर बनें। जहाँ लोग अवसर के लिए पलायन चुनें — इसलिए नहीं कि उनके गाँव में कोई अवसर नहीं है।

हमारा प्रथम सिद्धांत

कोई भी भारतीय जन्म से श्रेष्ठ नहीं है। कोई भी भारतीय जन्म से हीन नहीं है।

हर नागरिक समान गरिमा और कानून के समक्ष समान सुरक्षा का हकदार है। भारत का संवैधानिक ढांचा पहले से ही कानून के समक्ष समानता स्थापित करता है और निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हमारा उद्देश्य इन सिद्धांतों को शिक्षा, रोज़गार, सार्वजनिक सेवाओं और दैनिक प्रशासन में मूर्त रूप देना है।

- समान नागरिकता
- समान गरिमा
- समान अवसर
- कानून के समक्ष समान सुरक्षा
- वास्तविक विपन्नता के लिए साक्ष्य-आधारित सहायता

हम सामाजिक श्रेष्ठता के नए रूप बनाकर भविष्य नहीं बनाएंगे।

भाग I — नया सरकारी अनुबंध

सरकार का अस्तित्व है: सुरक्षा करना। शिक्षित करना। सशक्त बनाना। निष्पक्ष नियम बनाना। बुनियादी ढांचा बनाना। आवश्यक सेवाएँ देना। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। देश की रक्षा करना।

सरकार का अस्तित्व नागरिकों को स्थायी रूप से सरकार पर निर्भर बनाने के लिए नहीं है।

सरकार सशक्त बनाती है → नागरिक निर्माण करते हैं → समुदाय समृद्ध होते हैं

भाग II — भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता

सार्वजनिक पद सार्वजनिक विश्वास है।

भ्रष्टाचार को भारतीय जीवन की अपरिहार्य विशेषता नहीं माना जाएगा। लक्ष्य है: भ्रष्टाचार करना कठिन, छिपाना कठिन, पकड़ना आसान और कानूनी परिणामों से बंधा हुआ।

भ्रष्टाचार के लिए कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा। लेकिन साथ ही: उचित प्रक्रिया के बिना कोई दंड नहीं। आरोप ही दोषसिद्धि नहीं है। प्रणाली यह अंतर बनाए रखेगी:

शिकायत → जांच → अभियोजन → विचारण → दोषसिद्धि

सार्वजनिक धन सिद्धांत

करदाता का धन → बजट आवंटन → रिलीज़ → निविदा → अनुबंध → भुगतान → भौतिक डिलीवरी → स्वतंत्र सत्यापन → परिणाम

राष्ट्रीय सार्वजनिक व्यय बही (LEDGER)

हम सरकारी वित्तीय प्रणालियों, डिजिटल हस्ताक्षरों, क्रिप्टोग्राफ़िक ऑडिट ट्रेल, सुरक्षित डेटाबेस, स्वचालित विसंगति पहचान, स्वतंत्र ऑडिट और — जहाँ वास्तविक ऑडिट मूल्य हो — वितरित-बही प्रौद्योगिकी का उपयोग करके एक सुरक्षित सार्वजनिक-व्यय संरचना विकसित करेंगे। हम ब्लॉकचेन को नारे के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि पारंपरिक सुरक्षित डेटाबेस बेहतर है, तो हम वही उपयोग करेंगे। प्रौद्योगिकी पारदर्शिता की सेवा करेगी।

भ्रष्टाचार जोखिम प्रणाली

- अस्पष्ट लागत वृद्धि
- खरीद विसंगतियाँ
- बार-बार देरी
- ठेकेदारों का केंद्रीकरण
- असामान्य भुगतान पैटर्न
- बार-बार ऑडिट आपत्तियाँ
- हित-टकराव के संकेत

व्हिसलब्लोअर सुरक्षा

गोपनीय रिपोर्टिंग → केस नंबर → जांच की स्थिति → एस्केलेशन → कानून के अधीन प्रतिशोध से सुरक्षा

स्वच्छ राजनीतिक संगठन

आंदोलन को स्वयं वे मानक अपनाने होंगे जो वह सरकार से माँगता है। अपने वित्त, चंदे, व्यय, नेतृत्व चुनाव, हित-टकराव, उम्मीदवार चयन और आंतरिक अनुशासन प्रक्रियाएँ पारदर्शी नियमों और लागू कानून से संचालित होंगी।

हम ऐसी पार्टी नहीं बनाएंगे जो स्वयं अपना शासन नहीं कर सकती।

भाग III — भारत की सबसे बड़ी संपत्ति: उसके लोग

सबसे बड़ा राष्ट्रीय संसाधन भूमि, खनिज या इमारतें नहीं हैं। वह है मानवीय क्षमता।

रटना → परीक्षा → प्रमाणपत्र

को बदलकर बनाना है:

सीखना → समझना → प्रयोग → सृजन → उपयोग

भाग IV — टीन एनेक्स

समाज परिभाषित करे, उससे पहले क्षमता को खोजें।

हर बच्चा एक ही तरह से असाधारण नहीं होता। कोई गणित, विज्ञान, कोडिंग, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, संगीत, खेल, उद्यमिता, कृषि, चिकित्सा, लेखन, फ़िल्म-निर्माण, अनुसंधान, शिल्पकला, नेतृत्व या समस्या-समाधान में प्रतिभाशाली हो सकता है। टीन एनेक्स किशोरों को एक संरचित वातावरण देगा जहाँ वे जान सकें कि वे क्या करने में सक्षम हैं।

टैलेंट सेंडबॉक्स

- निर्माण — भौतिक और डिजिटल परियोजनाएँ
- प्रयोग — विचारों का परीक्षण
- असफलता — स्थायी लेबल के बिना सीखना
- सहयोग — अन्य छात्रों के साथ काम
- प्रतिस्पर्धा — राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चुनौतियाँ
- प्रस्तुति — अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन

टीन एनेक्स लैब्स

- प्रौद्योगिकी — AI, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स
- विज्ञान — भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान
- मेकर — 3D प्रिंटिंग, फ़ैब्रिकेशन, यांत्रिक प्रणालियाँ
- कृषि — मिट्टी विज्ञान, सेंसर, ड्रोन, हाइड्रोपोनिक्स
- डिज़ाइन — वास्तुकला, फ़ैशन, उत्पाद और ग्राफ़िक डिज़ाइन
- व्यापार — उद्यमिता, वित्त और विपणन
- सृजनात्मक — फ़िल्म, संगीत, फ़ोटोग्राफी और प्रदर्शन कला
- नागरिक नवाचार — छात्र वास्तविक सामुदायिक समस्याएँ सुलझाते हैं

राष्ट्रीय प्रतिभा पासपोर्ट

इस प्रणाली में भाग लेने वाले छात्र एक सुरक्षित डिजिटल पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें परियोजनाएँ, कौशल, प्रमाणपत्र, प्रतियोगिताएँ, अनुसंधान, प्रोटोटाइप, इंटरनशिप और सामुदायिक कार्य शामिल हों। यह औपचारिक शैक्षणिक योग्यताओं का पूरक है, विकल्प नहीं।

भाग V — स्टूडेंट सिटीज़

शिक्षा, सृजन और नवाचार के इर्द-गिर्द बने शहर।

स्टूडेंट सिटीज़ में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, प्रयोगशालाएँ, छात्र आवास, खेल, कला, स्वास्थ्य सेवा, इनक्यूबेटर, मेकर स्पेस, कंपनियाँ और सार्वजनिक स्थान एक साथ जुड़ेंगे।

छात्र → शोधकर्ता → निर्माता → उद्यमी → पेशेवर

विशिष्ट स्टूडेंट सिटीज़

- AI और प्रौद्योगिकी
- चिकित्सा अनुसंधान
- कृषि और खाद्य
- जल और जलवायु
- रक्षा प्रौद्योगिकी
- विनिर्माण और रोबोटिक्स
- डिज़ाइन और सृजनात्मक उद्योग

भाग VI — हर बच्चे को सक्षम शिक्षक का अधिकार

सरकारी नौकरी व्यावसायिक जवाबदेही समाप्त नहीं करनी चाहिए। एक शिक्षक होना चाहिए: योग्य + सक्षम + नैतिक + उपस्थित + निरंतर सुधार करता हुआ।

राष्ट्रीय शिक्षक सक्षमता प्रमाणन

सरकारी शिक्षकों का क्रमशः उनके विषय और स्तर के अनुरूप स्वतंत्र सक्षमता मूल्यांकन होगा: विषय ज्ञान, भाषा और संख्या-कौशल, शिक्षणशास्त्र, कक्षा क्षमता, बाल सुरक्षा और व्यावसायिक आचरण। गणित का शिक्षक गणित दिखाए, विज्ञान का शिक्षक विज्ञान दिखाए — और हर शिक्षक केवल उत्तर देना नहीं, पढ़ाने की क्षमता दिखाए।

शिक्षक सुधार (REMEDICATION)

- पहली असफलता: निदान + प्रशिक्षण
- दूसरी: गहन सुधार + पुनर्मूल्यांकन
- निरंतर असफलता: स्वतंत्र सक्षमता समीक्षा

नौकरी की सुरक्षा, व्यावसायिक मानकों से छूट नहीं है।

मास्टर टीचर कार्यक्रम

असाधारण शिक्षक बनेंगे: मेंटर, शिक्षक-प्रशिक्षक, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ और विद्यालय सुधार नेता। व्यावसायिक वृद्धि सक्षमता को पुरस्कृत करेगी।

भाग VII — विलेज इंडिया 2.0 — 90-दिवसीय ग्राम परिवर्तन कार्यक्रम

हमारे गाँवों को केवल शहरों के लिए श्रम का स्रोत नहीं माना जाना चाहिए। गाँव बनना चाहिए: रहने + सीखने + काम करने + निर्माण करने + निवेश करने की जगह।

5 गाँव। 5 बहु-विषयक टीमों। 90 दिन।

टीमों शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इंजीनियरिंग, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी, वित्त और पर्यावरण पर काम करेंगी।

ग्राम मानव पूंजी सूचकांक

हर वर्ष मापा जाएगा: सीखना, रोज़गार, घरेलू आय, उद्यम सृजन, स्वास्थ्य सेवा पहुँच, जल, ऊर्जा, इंटरनेट, महिलाओं की भागीदारी, कृषि और पर्यावरण।

जो मापा जाता है, वही प्रबंधित होता है।

ग्राम संसद

प्रस्ताव → बजट → जिम्मेदार प्राधिकरण → समय-सीमा → स्थिति

भाग VIII — बिना मजबूर पलायन के रोज़गार

हम पलायन का विरोध नहीं करते। हम उस स्थिति का विरोध करते हैं जिसमें पलायन अवसर का एकमात्र रास्ता हो।

ग्राम उद्यम क्षेत्र

खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, हस्तशिल्प, विनिर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, डिजिटल सेवाएँ, रसद, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, ग्रामीण BPO और सृजनात्मक उद्योगों में स्थानीय आर्थिक समूह विकसित किए जाएंगे।

ज़िला उद्यम केंद्र

विचार → पंजीकरण → वित्त → उत्पाद → ग्राहक → विस्तार

भाग IX — फ़ार्मर 2.0

किसान केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता नहीं रहना चाहिए।

किसान → उत्पादक → प्रसंस्करणकर्ता → ब्रांड → बाज़ार

विकसित किया जाएगा: कोल्ड चेन, भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण, सटीक कृषि, मिट्टी बुद्धिमत्ता, मौसम बुद्धिमत्ता, डिजिटल बाज़ार और किसान संगठन।

भाग X — राष्ट्रीय जल सुरक्षा

जल एक रणनीतिक राष्ट्रीय संसाधन है। लेकिन जल शासन को संवैधानिक दायित्व-वितरण और अंतरराज्यीय हितों का सम्मान करना होगा।

एक राष्ट्रीय जल रणनीति + वैज्ञानिक नदी-बेसिन प्रबंधन + राज्य सहयोग + स्थानीय क्रियान्वयन।

इंडिया वॉटर ग्रिड

जहाँ वैज्ञानिक रूप से उचित हो, जोड़ा जाएगा: नदियाँ, जलाशय, नहरें, आर्द्रभूमि, भूजल, रिचार्ज और पाइपलाइनें। उपयोग होगा: उपग्रह, GIS, सेंसर, भूजल निगरानी, वर्षा डेटा और AI पूर्वानुमान। हर प्रमुख बेसिन को मिलेगा एक जल संतुलन (Water Balance)।

कोई भी नदी असीमित पाइपलाइन नहीं है। अंतर-बेसिन स्थानांतरण में पारिस्थितिक प्रवाह, निचले समुदाय, भूजल, जैव-विविधता, बाढ़ जोखिम, जलवायु परिवर्तन और अंतरराज्यीय हित शामिल होंगे।

भाग XI — स्वच्छ नदियाँ

प्रमुख नदियों में शून्य अनुपचारित सीवेज।

सीवेज → उपचार → पुनः उपयोग

ना कि:

सीवेज → नदी

नदी स्वास्थ्य सूचकांक

निगरानी होगी: प्रदूषण, घुलित ऑक्सीजन, भारी धातुएँ, प्लास्टिक, जैव-विविधता, निष्कर्षण और पारिस्थितिक प्रवाह।

भाग XII — वन राष्ट्रीय पूंजी हैं

प्राकृतिक वनों का कोई अनावश्यक विनाश नहीं।

किसी महत्वपूर्ण वन परिदृश्य को प्रभावित करने से पहले जाँच होगी: वैकल्पिक मार्ग, क्षयग्रस्त भूमि, ब्राउनफ़ील्ड भूमि, मौजूदा गलियारे, उन्नत निर्माण, तकनीकी रूप से संभव हो तो सुरंग।

राष्ट्रीय पारिस्थितिक मानचित्र

- लाल — महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र
- नारंगी — उच्च पारिस्थितिक संवेदनशीलता
- हरा — प्रबंधित पारिस्थितिक परिदृश्य
- ग्रे — लागू स्वीकृतियों के अधीन संभावित विकास क्षेत्र

भाग XIII — जलवायु सुरक्षा

जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है। यह है: जल सुरक्षा + खाद्य सुरक्षा + स्वास्थ्य सुरक्षा + बुनियादी ढांचा सुरक्षा + आर्थिक सुरक्षा।

ज़िला जलवायु मानचित्र

मानचित्रण होगा: गर्मी, बाढ़, सूखा, दावानल, जल तनाव, फ़सल भेद्यता, तटीय जोखिम और बुनियादी ढांचा जोखिम। हर ज़िला एक दीर्घकालिक अनुकूलन योजना विकसित करेगा।

भाग XIV — मज़बूत भारत — आधुनिक रक्षा

क्षमता के माध्यम से शांति।

भारत को विश्वसनीय रक्षा क्षमता और रणनीतिक स्वायत्तता चाहिए। लक्ष्य: विश्व-स्तरीय + तकनीकी रूप से उन्नत + क्रमशः आत्मनिर्भर रक्षा।

पाँच रक्षा क्षेत्र

थल · वायु · समुद्री · अंतरिक्ष · साइबर

रक्षा प्रौद्योगिकी मिशन

सशस्त्र बल, DRDO, विश्वविद्यालय, स्टार्टअप और उद्योग को जोड़ा जाएगा। फ़ोकस: AI, ड्रोन, रोबोटिक्स, साइबर, सुरक्षित संचार, सेमीकंडक्टर, एयरोस्पेस, प्रोपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफ़ेयर और उपग्रह प्रणालियाँ।

वेटरन्स (भूतपूर्व सैनिक)

संरचित सहायता: स्वास्थ्य सेवा + पुनर्वास + शिक्षा + रोज़गार संक्रमण + उद्यमिता + पारिवारिक सहायता।

भाग XV — ऊर्जा-सुरक्षित भारत

उपयुक्त संयोजन विकसित किए जाएंगे: सौर, बायोमास, स्टोरेज, कुशल ग्रिड और कचरा-से-ऊर्जा।

ऊर्जा → कम लागत → उद्यम → रोज़गार

भाग XVI — डिजिटल सरकार

डिफ़ॉल्ट रूप से डिजिटल। आवश्यकता पर मानवीय।

आवेदन → अधिकारी → समय-सीमा → निर्णय → अपील

हर सेवा-लेनदेन के लिए एक डिजिटल ट्रैकिंग — नागरिक की सारी जानकारी वाली एक पहचान नहीं, बल्कि हर सरकारी सेवा के लिए एक सुरक्षित ट्रैकिंग प्रणाली। गोपनीयता और साइबर सुरक्षा अनिवार्य रहेंगी।

भाग XVII — महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता

मापा जाएगा: रोज़गार, उद्यमिता, संपत्ति स्वामित्व, शिक्षा, वित्त, परिवहन, सुरक्षा, बाल-देखभाल और स्वास्थ्य सेवा।

समुदायों को क्रमशः मिलेगा: मातृ स्वास्थ्य, बाल-देखभाल, पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, सुरक्षित परिवहन और लचीले-कार्य बुनियादी ढांचा।

भाग XVIII — राष्ट्रीय युवा शासन कोर

युवा पेशेवर काम कर सकते हैं: गाँव, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु, कृषि, प्रौद्योगिकी, लोक प्रशासन, अनुसंधान और उद्यमिता।

युवाओं को केवल चुनावी वर्ग नहीं माना जाना चाहिए।

युवा राष्ट्रीय क्षमता है।

भाग XIX — वैश्विक नीति प्रयोगशाला

भारत दुनिया भर की सफल प्रणालियों का निरंतर अध्ययन करेगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, परिवहन, डिजिटल शासन, कृषि, ऊर्जा, आवास, व्यावसायिक शिक्षा, कचरा और शहरी नियोजन।

अध्ययन → पायलट → मापन → अनुकूलन → विस्तार

हम दुनिया से सीखेंगे, लेकिन अंधानुकरण नहीं करेंगे।

भाग XX — पाँच राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणालियाँ

- रक्षा सुरक्षा — संप्रभुता की रक्षा
- जल सुरक्षा — दीर्घकालिक जल उपलब्धता
- खाद्य सुरक्षा — कृषि उत्पादकता की रक्षा
- ऊर्जा सुरक्षा — विश्वसनीय ऊर्जा
- जलवायु और पारिस्थितिक सुरक्षा — प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा

इन सबके नीचे: मानव सुरक्षा — शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, आवास, सुरक्षा और गरिमा।

भाग XXI — सरकारी स्कोरकार्ड

हर वर्ष सरकार एक सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट प्रकाशित करेगी।

- शिक्षा — क्या बच्चे सीख रहे हैं?
- शिक्षक — क्या शिक्षक सक्षम हैं?
- रोज़गार — क्या टिकाऊ नौकरियाँ बन रही हैं?
- स्वास्थ्य — क्या नागरिकों को समय पर देखभाल मिल रही है?
- जल — क्या जल सुरक्षा सुधर रही है?
- नदियाँ — क्या नदियाँ स्वस्थ हो रही हैं?
- वन — क्या महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित हैं?
- जलवायु — क्या समुदाय अधिक लचीले हो रहे हैं?
- रक्षा — क्या रणनीतिक क्षमताएँ बढ़ रही हैं?
- शासन — क्या सार्वजनिक धन का पता लगाया जा सकता है?
- गाँव — क्या स्थानीय अर्थव्यवस्थाएँ मज़बूत हो रही हैं?

भाग XXII — 100-दिवसीय सरकार

पहले 100 दिन दीर्घकालिक सुधार की मशीनरी स्थापित करेंगे।

- राष्ट्रीय सुधार डिलीवरी कार्यालय का गठन
- 90-दिवसीय ग्राम परिवर्तन पायलट शुरू
- शिक्षक सक्षमता ढांचा स्थापित
- सार्वजनिक व्यय बही पायलट शुरू
- राष्ट्रीय नदी-बेसिन डेटा एकीकरण शुरू
- राष्ट्रीय पारिस्थितिक मानचित्रण शुरू
- रक्षा प्रौद्योगिकी चैलेंज कार्यक्रम शुरू
- ज़िला उद्यम केंद्र पायलट शुरू
- ज़िला जलवायु-जोखिम मानचित्रण शुरू
- टीन एनेक्स पायलट नेटवर्क स्थापित
- स्टूडेंट सिटीज़ के स्थान और परिचालन मॉडल चिन्हित
- पहला सरकारी परिणाम डैशबोर्ड प्रकाशित

भाग XXIII — 1-3-5-10 वर्ष का रोडमैप

वर्ष 1 — प्रणाली बनाएँ

संस्थागत ढांचा, आधार-रेखाएँ, पायलट कार्यक्रम, डिजिटल ट्रेकिंग, शिक्षक सक्षमता मानक, ग्राम परिवर्तन पायलट और टीन एनेक्स पायलट।

वर्ष 3 — जो काम करे, उसे बढ़ाएँ

मापने योग्य परिणाम दिखाने वाले कार्यक्रमों का विस्तार। केवल राजनीतिक लोकप्रियता के आधार पर विस्तार नहीं।

पायलट → साक्ष्य → विस्तार

वर्ष 5 — राष्ट्रीय डिलीवरी

प्रमुख प्रणालियाँ राष्ट्रीय या व्यापक राज्य स्तर पर संचालित: शिक्षक सक्षमता, सार्वजनिक व्यय ट्रेकिंग, ग्राम परिवर्तन, उद्यम केंद्र, जलवायु मानचित्रण, जल निगरानी, नदी पुनरुद्धार और प्रतिभा विकास।

वर्ष 10 — मापने योग्य परिवर्तन

भारत सीखने, रोज़गार, आय, स्वास्थ्य, जल, पर्यावरण, जलवायु लचीलापन, रक्षा क्षमता और सरकारी जवाबदेही में मापने योग्य प्रगति दिखा सकेगा।

भाग XXIV — राजकोषीय नियम

हर बड़े वादे में बताना होगा: इसकी लागत क्या है, कौन भुगतान करेगा, कैसे लागू होगा, यह क्या बदलता या सुधारता है, क्या परिणाम आएगा, और इसकी ऑडिट कैसे होगी।

किसी चीज़ को इसलिए 'मुफ्त' नहीं कहेंगे क्योंकि नागरिक सेवा के समय भुगतान नहीं करता।

सार्वजनिक खर्च नागरिक का धन है।

भाग XXV — हमारा नीति फ़िल्टर

कोई भी बड़ी नई योजना स्वीकृत होने से पहले, सरकार को जवाब देना होगा:

- हम कौन-सी समस्या सुलझा रहे हैं?
- समस्या कितनी बड़ी है?
- क्या कोई मौजूदा कार्यक्रम इसे संबोधित करता है?
- क्या मौजूदा कार्यक्रम ठीक किया जा सकता है?
- जिम्मेदार कौन है?
- लागत क्या होगी?
- भ्रष्टाचार कैसे रोका जाएगा?

- मापने योग्य परिणाम क्या है?
- स्वतंत्र सत्यापन कौन करेगा?
- असफलता पर क्या होगा?

भाग XXVI — वह भारत जो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं

ऐसा देश जहाँ बच्चा जन्मस्थान के बावजूद सीख सके। शिक्षक सक्षमता के कारण सम्मानित हो। किशोर करियर चुनने से पहले अपनी प्रतिभा खोज सके। छात्र परीक्षा कक्ष के साथ प्रयोगशाला में जा सके। किसान कंपनी बना सके। गाँव रोज़गार पैदा करे। महिला स्वतंत्र आर्थिक जीवन बना सके। नागरिक सरकारी सेवाओं को ट्रैक कर सके। करदाता देख सके कि सार्वजनिक धन कहाँ जाता है। भ्रष्ट अधिकारी राजनीतिक संबंधों के पीछे न छिप सके। नदी जीवित राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाए। वन नष्ट करने योग्य न माना जाए। जल की वैज्ञानिक योजना हो। ऊर्जा सुरक्षित हो। सशस्त्र बलों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी हो। भारतीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करें। युवा राष्ट्र-निर्माण में भाग लें।

और सरकार का मूल्यांकन होगा परिणामों से — घोषणाओं से नहीं।

भाग XXVII — फ़्यूचर इंडिया समीकरण

समान नागरिकता + विश्व-स्तरीय शिक्षा + प्रतिभा विकास + स्थानीय रोज़गार + मज़बूत रक्षा + जल सुरक्षा + स्वच्छ नदियाँ + संरक्षित वन + जलवायु लचीलापन + ऊर्जा सुरक्षा + भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता + जवाबदेह सरकार + युवा-नेतृत्व वाला नवाचार

= फ़्यूचर इंडिया 2047

हमारा अंतिम सिद्धांत

हम यह वादा नहीं करते कि सरकार हर व्यक्ति को खुश कर सकती है। हम यह वादा करते हैं कि हम ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे जिनमें लोग अपना जीवन स्वयं बनाने की अधिक मज़बूत क्षमता रखें।

सरकार बनाएगी: सुरक्षा, अवसर, बुनियादी ढांचा, ज्ञान, निष्पक्ष नियम, जवाबदेही।

फिर नागरिक बनाएंगे: व्यापार, परिवार, समुदाय, विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी, रोज़गार — एक भविष्य।

अंतिम राष्ट्रीय दृष्टि

ऐसा भारत जहाँ आपका जन्म आपकी नियति तय नहीं करता।

ऐसा भारत जहाँ आपका गाँव आपके भविष्य को सीमित नहीं करता।

ऐसा भारत जहाँ आपकी सरकार आपका धन नहीं छिपा सकती।

ऐसा भारत जहाँ आपका बच्चा खोज सके कि वह क्या बन सकता है।

ऐसा भारत जो स्वयं की रक्षा के लिए पर्याप्त मज़बूत हो।

अपने जल और वनों की रक्षा के लिए पर्याप्त समझदार हो।

अपनी सरकार को मापने के लिए पर्याप्त अनुशासित हो।

और 2047 के लिए निर्माण की महत्वाकांक्षा रखे — केवल अगले चुनाव के लिए नहीं।

फ़्यूचर इंडिया 2047

क्षमता से सामर्थ्य तक।

सामर्थ्य से सृजन तक।

सृजन से राष्ट्रीय प्रगति तक।